www.sadinama.in

सदीनामा

सोच में इज़ाफा

ISSN : 2454-2121

वर्ष-19 ❍ अंक-11 ❍1 से 30 सितम्बर 2019❍ पृष्ठ-28 ❍ R.N.I. No. WBHIND/2000/1974 ❍मूल्य - 10 रूपये

अमेजन के जंगलों में आग

Scanned by CamScanner

याद की गई चूनी कोटाल, 17 अगस्त 2019

कृष्णपद घोष मेमोरियल ट्रस्ट, कलकत्ता

विषय : पेरियार राम स्वामी नायकर का आत्म सम्मान आन्दोलन

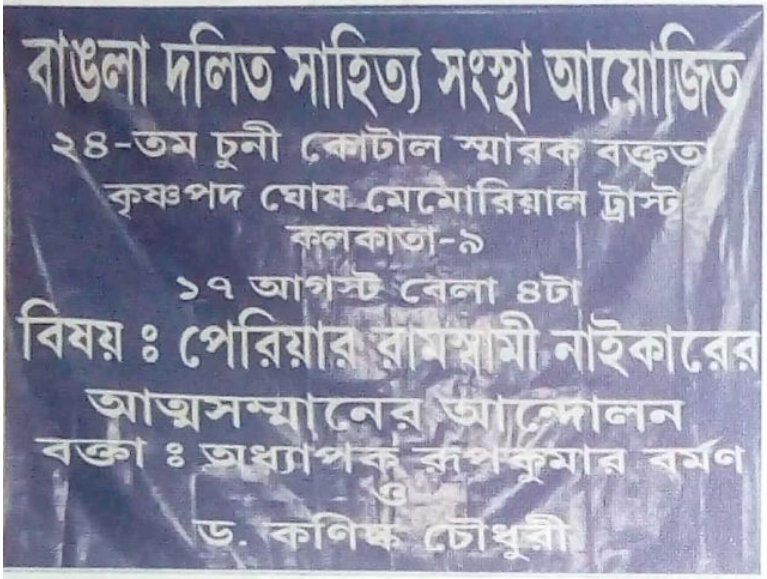

Scanned by CamScanner

कहाँ सोये पड़े हैं मालिक?

भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में आम आदमी ही इस देश का मालिक है। सारी व्यवस्था इसी के इर्द गिर्द घूमती है। आजादी के बाद यही आम आदमी हमारे केन्द्र में था और आज भी है। पर पिछले कुछ दिनों से इस आदमी के आस-पास बहुत कुछ बदल रहा है जिसको यह समझ नहीं पा रहा है। इन बदलावों में सबसे ज्यादा है इस आदमी के स्वामित्व का बदलना जिन संस्थानों के ऊपर तिरंग झंडा लगा है या अशोक स्तम्भ है वही सरकारी संपत्ति है इस सरकारी संपत्ति का घट जाना राष्ट्र की स्थिति दर्शाता है। सरकारें अपनी योजनाओं और स्थितियों के अनुसार इनका मालिकाना बदलने लगती है। जिसके कारण यह निगमों में बदलने लगते हैं। निगम बाद में प्राइवेट होने लगते हैं।

आज दर्जन भर निगम बिकने तैयार हैं। इनको खरीदने की औकात सबकी नहीं, कोई मोटा सेठ ही इनको खरीद सकता है। बंगाल में किसी जमाने में एक जूट मिल का राष्ट्रीयकरण किया गया था सबको लगाता था अब कारखानों की दशा दुरुस्त हो जाएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकारी लालफीताशाही और अफसरशाही ने इस जूट मिल को ठीक से चलने नहीं दिया और आज यह जूट मिल बंद हो गया। किसी जमाने में सरकारीकरण दवा माना जाता था। आज ठीक उल्टा है, सरकारी संस्थान पहले निगमीकरण होते हैं और इसके बाद यह बता करके कि बहुत घाटा हो रहा है इनको प्राइवेट के हाथ बेच दिया जाता है। यह प्रक्रिया आजकल जोरों पर हैं।

सरकारी बैंकों में भी इन दिनों काफी उथल-पुथल मची हुई है। सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों से आँकड़े लिए जा रहें हैं और यह कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर बंकों के कार्य निष्पादन की समीक्षा होगी, अच्छी बात है जरूर होनी चाहिए पर इसका प्रभाव यह न हो कि बैंकों की पहचानें खत्म हो जायें और फैसले लेना ठप्प हो जाये। ये काम जोरों पर है और मालिक और आप सो रहे हैं।

स्व॰ इन्दिरा गांधी के द्वारा बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद प्राइवेट बैंकों के लाइसेंस बंद कर दिये गये थे पर धीरे-धीरे फिर प्राइवेट बैंक आने लग गए हैं सरकारी बैंकों की शाखाएँ तेजी से घट रही हैं इन बैंकों में शाखाओं के अनुसार पद बनाए जाते हैं एक बैंक के कम होने से उसमें काम करने वाले लोगों के पदों की संख्या भी घट जाती है यह काम बहुत धीरे-धीरे हो रहा है और मालिक आप सो रहे हैं। सरकारी सरकारी गीत आप भूल जाइए और प्राइवेट प्राइवेट कहिए। अमेरिका में एक बैंक हुआ करती थी जिसका नाम था लेहमन बैंक 200 साल की पुरानी यह बैंक अपनी तमाम योजनाओं के बावजूद दिवालिया हो गई और इसके नक्शे कदम पर चलनेवाली तमाम बैंक बंद हो गयीं और हजारों की संख्या में लोग फुटपाथ पर पहुँच गये। हुआ कुछ इस क्रेडिट कार्ड को आधार बनाकर बैंक लोन दिए जाने लगे कुछ बैकों में कुछ ऐसे मैनेजर आए जिन्होंने बैंक का ज्यादा काम दिखाने के लिए लोगों को सहज ही बैंक कर्ज दिए जब ईएमआई का समय आया तो एक व्यक्ति पांच जगह ईएमआई नहीं दे सकता था और जब वसूली का समय आया तो वसूलने के लिए ज्यादा कुछ था नहीं जिनके पास फ्लैट्स थे वह एक बैंक ने ले लिये लेकिन बाकी के बैकों लिए कुछ नहीं था नतीजा हुआ कि बैंकों का अपनी लाखों की संपत्ति गंवानी पड़ी और दिवालिया हो गए। भारत में भी बहुत सारे बैंक दिवालिया हुए जिनके

Scanned by CamScanner

कारण अलग-अलग थे पर यह कारण अमेरिका से पूरी तरह अलग थे। असल में एक जटिल मामला है बिना बेहतर अर्थशास्त्रियों की टीम के कोई भी वित्त मंत्री देश की लंबी योजनाएँ नहीं बना सकता। आर्थिक नीतियों को बनाने वाले अफसर हमेशा अपने मंत्री के विवेक पर चलने के लिए बाध्य है।

भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है 'रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया' जिसके बाद पास बहुत सारा रिजर्व फण्ड है। इस बैंक की स्वायतत्ता ने भारत को आर्थिक तौर पर दुनिया में आयी तमाम मंदी के बावजूद बचा लिया। पर अब इस बैंक की स्वायतत्ता को बचाने के लिए आपके अधिकारी आपकी सरकार को समझा रहे हैं, और, कितना समझा पाएंगे, पता नहीं, पर साहब आप तो सोये पड़े हैं । मालिक आप ही इस देश को बचा सकते हैं। उठिये, जागिए कुछ करिए नहीं तो बाद में कहने को ज्यादा कुछ नहीं बचेगा। अगर आपको लगता है कि जो हो रहा है वह सच है या नहीं तो अपने आंख नाक कान खुले रखिए। वैकल्पिक मीडिया को जिंदा रखिए। हमने सदीनामा में कुछ दिन पहले अपनी सरकार के चलने वाली 101 योजनाओं के बारे में लिखा था। इनमें कुछ योजनाओं में गया पैसा वापस नहीं आ रहा है इन पैसों से होनेवाली हानि की भरपाई कैसे होगी ? लगता तो नहीं इस पर भारपाई के लिए सरकार अपने रिजर्व फंड को प्रयोग करना चाहती है, जिससे होने वाली कमाई घाटे में जाने वाली है। हम सरकार की योजनाओं का समर्थन करते हैं साथ ही यह भी चाहते कि राष्ट्र के प्रति शुरु हुई तमाम गतिविधियां चाहे वह आर्थिक ही हो क्यों न हो उन पर सरकार लगाम लगाए और हमें उम्मीद है मालिक आप भी यही चाहते होंगे।

जीतेन्द्र जितांशु

jjitanshu@yahoo.com

पत्रिका का ताना-बाना

संपादक

जीतेन्द्र जितांशु

9231845289

सम्पादकीय सलाहकार

यदुनाथ सेउटा

उप-सम्पादक

तितिक्षा

मिनाक्षी सांगानेरिया

संरक्षक मंडल :

आरती चक्रवर्ती

एच॰ विश्ववाणी

शिवेन्द्र मिश्र

राजेन्द्र कुमार रुइयां (अमेरिका)

डीटीपी, लेआउट तथा भूल-सुधार

रमेश कुमार कुम्हार

राजेश्वर राय

मारिया शमीम

कवर पेज कलर का चुनाव :

उषा सिंह, दिल्ली

केहु के कुछो ना दिहल जाला

मनीऑर्डर तथा पत्राचार का पता :

संपादक - सदीनामा

PURBAYAN

38E, Prince Bakhtiar Sah Road

Kolkata - 700 033

West Bengal

E-Mail : sadinama2000@gmail.com

Scanned by CamScanner

हड़ताल की पूर्व पीठिका

पूर्व सीओएएस, जनरल, वी.पी. मलिक ने 'आर्मिंग द इंडियन आर्सेनल' के प्राक्कथन में उल्लेख किया हैं, कि आयुध निर्माणियों ने मौके पर पहुँचकर अपनी तकनीक के साथ गोला-बारूद और उपकरण प्रदान किए, लेकिन हमें उन वस्तुओं की खरीद में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिन्हें शॉर्ट नोटिस पर आयात किया था। दिसम्बर 2000 में नायर समिति ने तत्कालीन एमजीओ को आयुध कारखानों के सराहनीय प्रदर्शन के लिए बधाई दी है और उल्लेख किया है कि परिचालन के दौरान विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से आपूर्ति अविश्वसनीय है। DCOAS (P & S) ने कहा कि रक्षा तैयारी के लिए ओएफबी का अस्तित्व सैन्य तैयारी के लिए जरूरी है। कैग के रिपोर्ट के अनुसार कारगिल संघर्ष के दौरान 129 अनुबंधों में से 2175.40 करोड़ रूपये का अनुबंध आयुध कारखानों के अलावा अन्य कारखानों पर किए गए तथा 81% आपूर्ति संचालन के समाप्त होने के छह महीने के बाद ही पूरी हो सकती थी। ओएफबी द्वारा किए गए आपूर्ति के लिए साथ-साथ एक भरोसेमंद, आपूर्तिकर्ता के रूप में भारतीय सशस्त्र बलों का नए सिरे से विश्वास हासिल किया। रेगिस्तान से लेकर ग्वालियर, घाटियों से लेकर पर्वतीय सेनाओं तक की आपूर्ति आयुध निर्माणियों द्वारा की गई है, जो हमारे सशस्त्र बलों को अपेक्षित शक्ति, पंच और बल प्रदान किया है।

यद्यपि आयुध निर्माणियों की क्षमता अनुमानत: बीस हजार करोड़ से अधिक का उत्पादन करने की है, लेकिन वर्तमान सरकार इस अवसर का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं है और कार्यभार बहुत कम कर दिया है, भर्ती पर प्रतिबंध लगा दिया है, और कृत्रिम रूप से इन निर्माणियों को कमजोर इकाइयों के रूप में चिह्नित करने की कोशिश की है।

वर्तमान एनडीए सरकार ने 41 आयुध निर्माणियों को निगमित करने के लिए सौ दिनों का एक लक्ष्य निर्धारित किया है और यह पता चला है कि सचिव (डीपी) ने रक्षा उत्पादन के संयुक्त सचिवों को निर्देश दिया है कि वे आयुध निर्माणियों के निगमीकरण के लिए नोट तैयार करें। यह पाया गया है कि फाइल प्रधानमंत्री कार्यालय में स्वीकृति के लिए पहुँच गयी है। निगम के प्रस्तावित ढाँचे के बारे में खबरें दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित होते हैं। इस योजना की कई विशेषताएँ हैं कहा जाता है कि वेतन और भत्ते के भुगतान के लिए बजटीय सहायता पांच साल तक दी जायेगी। 15 साल से अधिक सेवा देने वाले इच्छुक कर्मचारियों के लिए वीआरएस योजना, अगर निगम कोई नुकसान उठाता है तो 30% ऋण दिया जाएगा और 70% इक्विटी निवेश की अनुमति दी जाएगी, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई आरक्षण और निजी भागीदारी के साथ संयुक्त उद्यम को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा आदि।

हम इस बात से अवगत है कि बीएसएनएल, जो कॉरपोरेटीकरण के कारण सताया हुआ जान पड़ता है, और अब विभिन्न कोनों से बहुत दबाव का सामना कर रहा है । कर्मचारी अपना मासिक वेतन पाने के लिए संघर्ष कर रहे है। सरकार और दूरसंचार विभाग जियो, एयरटेल और वोडाफोन को सभी सहायता प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बीसएनल को वंचित किया जा रहा है। वीएसएनएल 4-जी स्पेक्ट्रम से वंचित है और निजी कम्पनियों को भी इसकी अनुमति दी गई है।

अतीत में श्री टी.ए. नायर और श्री विजय केलकर की अध्यक्षता में कुछ समितियों ने आयुध निर्माणियों को कॉरपोरेटाइज करने की सिफारिश की है, यूपीए सरकार ने मान्यता प्राप्त फेडरेशनों के नेतृत्व में राष्ट्रव्यापी कार्यबल के मजबूत विरोध के कारण इस प्रस्ताव पर ध्यान नहीं दिया है। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वर्तमान सरकार हिस्सेदारी धारकों से सलाह किए बिना इसकी सिफारिशों को लागू करने के लिए उत्सुक है।

सरकार का आयुध निर्माणियों को कॉरपोरेट करने का निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा के हित के विरुद्ध होगा क्योंकि हम अपने दुश्मनों की ओर से सीमाओं पर आतंकवाद का सामना कर रहे

Scanned by CamScanner

हैं। आयुध निर्माणियों को वाणिज्यिक संगठन नहीं माना जाना चाहिए और न ही लाभ अर्जित करने की दृष्टि देखना चाहिए। यदि इसे निजी कंपनियों के हाथों में सौंप दिया जाता है तो उनका उद्देश्य लाभ कमाना होगा, सिर्फ और सिर्फ अधिक से अधिक लाभ कमाना होगा और राष्ट्रीय सुरक्षा को नजरंदाज किया जाएगा।

चूँकि रक्षा सिविलियन कर्मचारियों ने अपने बैनरों और झंडों की परवाह किए बिना अपने विभिन्न प्रकार के आंदोलन शुरू कर दिए है और 20 अगस्त 2019 से राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने का प्रस्ताव है, जो केन्द्र सरकार को आयुध कारखानों के निगमीकरण करने के निर्णय को त्यागने पर बल देगा। आयुध निर्माणियों का निगमीकरण राष्ट्रीय सुरक्षा के हित और 82,000 समर्पित कार्यबल के हित के लिए घातक है। हम हमेशा आयुध निर्माणी संगठन के जवाबदेही बढ़ाने और उत्पादकता सुनिश्चित करने के तरीकों पर विचार करने के लिए तैयार है।

हमें उम्मीद है कि आप उपरोक्त लाइनों में व्यक्त की गई उस स्थिति की गंभीरता को समझ सकते हैं और इन सभी पर विचार कर आप अपने प्रिंट मीडिया / टेली मीडिया को संघर्षरत कार्यबल और राष्ट्र के हित के लिए भी विस्तारपूर्वक जगह देंगे।

AIDEF INDWF INDWF BPMS (CDRA)

Scanned by CamScanner